

co-operative societies. This scheme has not yet been introduced in Bihar. Such societies are not being financed by the commercial banks under this scheme in Saharsa District.

**कृषक बचत योजनाएँ**

6360. श्री खिरंजीब झा . क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार में हुई राष्ट्रीय बचत सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की गत बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने "कृषक बचत योजना" प्रारम्भ करने की मांग की थी; और यदि हा, तो यह कब तक लागू की जायेगी और इसका सक्षिप्त व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : 10 फरवरी 1973 को पटना में हुई केन्द्रीय राष्ट्रीय बचत सलाहकार बोर्ड की पिछली बैठक में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने उन किसानों का मनोबल ऊचा करने के उद्देश्य से, जो अपनी बचतों को भली भाँति नियोजित कर सकते हैं, "किसान बचन पत्र" चालू करने का सुझाव दिया था जिन्हें सहकारी समितियों आदि की मार्फत बेचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्तावों का व्यौरा प्राप्त होने पर इस सुझाव पर और आगे विचार किया जायेगा।

जून, 1972 के अन्तिम शुक्रवार को बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंको के द्वारा दिये गये अग्रिम :

(लाख रुपयों में)

खातो की स्वीकृत सीमा बकाया रकम सख्या

	(रुपये)	(रुपये)
कृषि*		
(क) सप्रत्यक्ष वित्त . . . . .	15065	351.43
(ख) अप्रत्यक्ष वित्त . . . . .	966	229.54
लघु उद्योग** . . . . .	1100	990.60
		592.11

\*अन्तिम आकड़े

\*\*अन्य उद्योगों को दिये गये अग्रिमों का विवरण अलग से उपलब्ध नहीं है ।

**बिहार में बैंकों की शाखाएं और औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों के लिए किए गए ऋण**

6361. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले बैंकों की कुल कितनी शाखाएं थी; और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कितनी शाखाएं खोली गई; और

(ख) वर्ष 1972 के दौरान बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों को क्रमशः कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) बिहार में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या जो 19 जुलाई, 1969 को 274 थी, बढ़कर दिसम्बर, 1972 के अन्त में 575 हो गयी।

(ख) उपलब्ध सूचना नीचे दी गयी है .—